प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन हमेशा मानव अस्तित्व का एक अभिन्न अंग रहा है। 19 वीं शताब्दी के बाद तेजी से हुए औद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ, जलवायु परिवर्तन ने एक नया आयाम हासिल कर लिया है, जिससे जीवन, आजीविका और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हुआ है। हाल के दशकों में चरम जलवायु घटनाओं की बढ़ती घटनाओं ने इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। बढ़ते वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधियों के कारण भी होता है, जैसे कि - जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक जलने का परिणाम; वनों की कटाई; अनुचित कृषि पद्धतियां आदि। अत: समन्वित नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता पर एक वैश्विक सहमति अनिवार्य हो गई है जिसमें अनुकूलन और शमन रणनीति, दोनों शामिल हों। 2016 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते के बाद से, जलवायु संबंधी विषय तेजी से लक्ष्य-उन्मुख हो गया है।

भारत ने अपने विकास और पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करते हुए एक महत्वाकांक्षी और लक्षित जलवायु कार्य योजना शुरू की है। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना और 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है। भारत ने सीओपी27 में अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की, जिसमें हरित हाइड्रोजन उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता और जैव ईंधन के बढ़ते उपयोग के विस्तार की योजनाएं शामिल हैं। समाधान-आधारित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और मिशन एलआईएफई (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरॉनमेंट) भी शुरू और पोषित किया है।

वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार जलवायु जोखिम की घटनाओं के जोखिम और संवेदनशीलता के मामले में भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में उच्च (सातवें) स्थान पर है, लेकिन वह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार अपने जलवायु संरक्षण प्रदर्शन में सबसे अधिक रैंक वाला जी -20 देश भी है। यह चार मापदंडों पर हुई प्रगति को परिलक्षित करता है - ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन; नवीकरणीय ऊर्जा; ऊर्जा का उपयोग; और जलवायु नीति। भारत जल्द ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसलिए, सफल हरित संक्रमण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण कच्चे माल तक पहुंच प्राप्त करते हुए चरम जलवायु घटनाओं के बीच खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को संरक्षित करना, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती बनी रहेगी।

देश की वृहत-वित्तीय संभावनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन प्रेरित जोखिम और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए उपलब्ध नीति विकल्पों के लिए समर्पित अनुसंधान की आवश्यकता है। जलवायु, अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रणालियों और संबंधित नीतियों के संचालन के तरीकों की जटिलता और भिन्नता के चलते इस तरह के शोध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए, मुद्रा और वित्त पर इस वर्ष की रिपोर्ट का विषय “एक हरित स्वच्छ भारत की ओर” है। चार अध्यायों में संरचित यह रिपोर्ट नीतिगत प्राथमिकता के रूप में जलवायु लक्ष्यों के महत्व पर प्रकाश डालती है और मध्यम से लंबी अवधि में भारत के लिए जलवायु परिवर्तन के व्यापक-वित्तीय प्रभावों की मीमांसा करती है। विकास, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए उपलब्ध नीतिगत विकल्पों - राजकोषीय नीति; टेक्नोलॉजी; व्यापार नीति; नियामक नीति; और मौद्रिक नीति – के तहत समाधान ढूंढे जाते हैं। इस रिपोर्ट में भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती के कुछ प्रमुख पहलुओं तथा भविष्य की स्थिति की मीमांसा करने के लिए मैं रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) दल की सराहना करता हूं। मुझे आशा है कि यह प्रतिवेदन इस विषय पर सार्वजनिक नीतिगत विमर्श को समृद्ध करेगा।

शक्तिकांत दास
गवर्नर
3 मई 2023